हे मूलचंद शर्मा...तुम डंफरों की ओवरलोडिंग नहीं रोक पाओगे

पेज एक का शेष

मंत्री मूलचंद शर्मा ने 11 ऐसे डंफरों को जब्त किया जो ओवरलोडेड थे यानी जिनमें तय मानक से ज्यादा रेता, बदरपुर, पत्थर आदि भरे हुए थे। बिना मास्क लगाए मंत्री मूलचंद अफसरों से इस मामले में जवाब तलब करते दिखे। मास्क लगाए हुए अफसर क्या जवाब देते। उन्हें पता है कि ये डंफर कैसे चलते हैं, कौन चलावाता है और कहां-कहां हिस्सा जाता है। लेकिन अफसरों ने मंत्री की पूरी तसल्ली कर दी। मूलचंद मौके पर किसी अफसर के खिलाफ एक्शन नहीं ले सके। न ही फरीदाबाद-गुड़गांव के संबंधित थानों-चौकी के पुलिस वालों को कुछ कह सके जिनकी जानकारी में डंफरों में ओवरलोडिंग का धंधा चल रहा है। डंफरों की ओवरलोडिंग की वजह से आये दिन हादसे होते रहते हैं।

मूलचंद डंफरों के गोरखधंधे को तब से जानते हैं, जब वो बल्लभगढ़ में दुकान पर बैठते थे। लेकिन बहरहाल अब मंत्री हैं तो उन्हें डंफरों के जरिए हो रहे भ्रष्टाचार की याद आई हो। लेकिन जब उन्होंने मंगलवार को यह कार्रवाई की तो जनता ने चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। चूंकि मंत्री सड़क किनारे इस तरह की चेकिंग कर रहे थे तो वहां से गुजरने वाले भी मंत्री पर जुमले कसते हुए निकल रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि मास्क क्या सिर्फ हमारे लिए हैं। मंत्री का मास्क कहां चला गया ? कुछ लोगों ने कहा कि डंफरों में ओवरलोडिंग कराने वाले भड़ाना तो आजकल भाजपा में ही हैं, मंत्री कैसे भाजपा नेताओं के ऐसे धंधों को बंद करा सकते हैं। कुछ ने प्रचलित मुहावरों का इस्तेमाल भी किया।

डंफरों पर लगाम ऐसे कहां लगेगी

मंत्री मूलचंद शर्मा अगर सोच रहे हैं कि उनके इस अचानक जांच पड़ताल और 11 डंफरों के जब्त करने से यह धंधा रुक जाएगा तो यह बात बचकानी है। फरीदाबाद-गुड़गांव में डंफरों की ओवरलोडिंग का धंधा बहुत संगठित तरीके से चल रहा है। जिसे मंत्री तो क्या मुख्यमंत्री तक रोक नहीं सकते। डंफरों के मालिक ज्यादातर सत्तारुढ़ पार्टी के लोग हैं। उन्हीं के पास माइंस (खानें) हैं, उन्हीं के पास क्रशर हैं, उन्हीं के पास भाजपा को मोटा चंदा देने और यहां तक की पार्टी का टिकट खरीद लेने का पैसा है। इस रास्ते पर हर चौकी और थाने को हर महीने मंथली पहुंचती है। वह मंथली कितनी ऊपर तक जाती होगी, उसके बारे में सब सर्वविदित है। आबकारी कराधान विभाग भी इन पर कार्रवाई कर सकता है लेकिन वहां के भी कुछ अफसरों का संरक्षण इस धंधे को मिला हुआ है। मंत्री मूलचंद ने पहल अच्छी की है लेकिन उनकी यह पहल भ्रष्ट अफसरों और भड़ाना नियंत्रित संगठित कारोबार के सामने सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह जाएगी। फरीदाबाद-गुड़गांव रोड पर अगर इन डंफरों की ओवरलोडिंग और स्पीड लिमिट पर लगाम लग जाए तो इस सड़क से गुजरने वाले हजारों बाइक-स्कूटी वाले मूलचंद को दुआएं जरूर देंगे। मंत्री मूलचंद कल को यह कहकर पल्ला छुड़ा सकते हैं कि उनके पास पुलिस विभाग नहीं है और सिर्फ पुलिस विभाग ही इन पर काबू पा सकता है तो यह जवाब सही नहीं होगा। मौजूदा पुलिस कमिश्नर की ईमानदारी के गीत गाये जा रहे हैं तो ऐसे में अगर इन डंफरों पर अब लगाम नहीं लगी तो कब लगेगी। ....पता नहीं मूलचंद शर्मा अगली बार मंत्री बनेंगे या नहीं लेकिन उन्हें हजारों बाइकों-स्कूटर वालों की दुआएं लेने के लिए पुलिस कमिश्नर से बात करके इस धंधे पर शिकंजा कसवाना चाहिए। वरना जनता इसे ड्रामा करार देते देर नहीं लगेगी।

मजदूर मोर्चा के पाठकों को याद होगा कि पिछले अंक में हमने मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा शहर की सड़कों का जायजा लेने के संबंध में खबर छापी थी। मूलचंद शर्मा की वह पहल अच्छी होने के बावजूद ड्रामा ही साबित हुई। फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) पूरी तरह कंगाल है। पैसे के अभाव में सड़कें बन ही नहीं सकतीं, ऐसे में अफसरों को बुलाकर सिर्फ आदेश देने भर से और अखबारों में गुड न्यूज छपवा भर देने से शहर की सड़कें नहीं बन पाएंगी। अगर मंत्री में हौसला है तो सिर्फ फरीदाबाद की सड़कों के लिए विशेष ग्रांट लेकर आयें। लेकिन वो स्पेशल ग्रांट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद अपनी घोषणा के तहत होने वाले विकास कार्यों पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। ऐसे में मूलचंद शर्मा के मुआयने भर से कुछ नहीं होने वाला।

नीलम पुल की मरम्मत...

पेज एक का शेष

है। लेकिन दरअसल एमसीएफ इस मामले में शहर की जनता से झूठ बोल रहा है। नीलम पुल के नीचे 22 अक्टूबर को कबाड़ में आग लग गई थी। इस आग से पुल के एक हिस्से के पिलर क्षतिग्रस्त हो गए थे। उस समय पुल को पूरी तरह बंद कर दिया गया लेकिन कुछ दिनों बाद उसके एक हिस्से को खोल दिया गया। लेकिन एक हिस्सा खोले जाने की वजह से मथुरा रोड से लेकर नीलम पुल के दूसरी तरफ तक भयंकर जाम लगा रहता है। खासकर सुबह और शाम को हालात बिगड़ जाते हैं। एमसीएफ के मुताबिक 25 लाख खर्च करके इस पुल की मरम्मत की जा सकती है लेकिन कोई ठेकेदार टेंडर उठाने को तैयार नहीं है। लेकिन यह सब लीपापोती है।

मेयर या मोम गुड़िया

शुरू से ही विवादों में घिरी फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला मोम की गुड़िया साबित हो रही हैं। वो शहर के विकास को लेकर जरा भी चिन्तित नहीं हैं न ही उनकी सक्रियता शहर के तमाम गतिविधियों में नजर आती है। नगर निगम को दी गई शक्तियों के मुताबिक मेयर के पास एक करोड़ से लेकर ढाई करोड़ तक का काम कराने का अधिकार है। लेकिन अगर वो नीलम पुल के लिए अपने इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो फिर किस काम के लिए करेंगी। लेकिन मेयर साहिबा एक बार भी मौका देखने नहीं गईं कि जनता वहां से किस हाल में निकलती है। उनका रवैया यह है कि शहर में एमसीएफ अफसर कुछ भी करते रहें, उनसे मतलब नहीं है। न ही वो उसमें देखल देने की ही हिम्मत जुटा पाती हैं। तमाम मामलों में भाजपा के विधायक और मंत्री सीधे टांग अड़ाकर एमसीएफ अफसरों से अपना काम करा लेते हैं और मेयर बस देखती रह जाती हैं।

निगम कमिश्नर को बंद कमरे का शौक

एमसीएफ कमिश्नर यश गर्ग को या तो इस शहर से नफरत है या फिर वो शहर को इस लायक नहीं पाते हैं कि अपने दफ्तर से बाहर निकलकर हालात का जायजा लें। अगर उन्होंने नीलम पुल का जायजा लिया होता तो अब तक इस पुल की मरम्मत हो चुकी होती। कमिश्नर एमसीएफ के पास एक करोड़ का काम कराने का अधिकार है। लेकिन यश गर्ग अपनी कुर्सी पर वो अधिकार लेकर बैठे हैं। मेयर की तरह एमसीएफ कमिश्नर यश गर्ग को भी शहर से कोई लगाव नहीं है। उनके चहेते कर्मचारी और भाजपा के चंद नेता जो कहते हैं, कमिश्नर उसी हिसाब से चलते हैं। शहर के किसी भी प्रोजेक्ट में उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल आज तक नहीं किया। एमसीएफ मुख्यालय में कई दफ्तर जर्जर हालत में हैं, कुछ में न जाने कितने वक्त से सफेदी तक नहीं हुई लेकिन अगर कमिश्नर ने अपने ही मुख्यालय का मुआयना किया होता तो शायद यह हाल न होता।

इनके पास भी हैं अधिकार

मेयर और कमिश्नर के अलावा इंजीनियरिंग, सिविल और अन्य विकास कार्य के लिए ज्वाइंट कमिश्नर एक महीने में अधिकतम 10 लाख और कार्यकारी अभियंता एक महीने में अधिकतम दो लाख के काम सीधे करा सकते हैं। लेकिन कार्यकारी अभियन्ता 25 लाख तक और अधिशासी अभियंता 25 लाख से 50 लाख तक और चीफ इंजीनियर 50 लाख से ऊपर का रेट होने पर कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत कर सकते हैं। एक तरह से इन अधिकारियों के पास भी नीलम पुल की मरम्मत जैसा महत्वपूर्ण काम कराने का अधिकार है। लेकिन चूंकि इनके ऊपर कमिश्नर और मेयर हैं तो ये अधिकारी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। इन्हें पूछना पड़ेगा। जिनकी अफसरों की आला अफसरों से सेटिंग होती है, उन्हें पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

कौन रोक रहा है नीलम पुल के काम को

दरअसल, फरीदाबाद की जनता की लाइफलाइन बन चुके इस पुल की मरम्मत की आड़ में एमसीएफ के अफसरों की नजर कहीं और है। वे चाहते हैं कि विधायक और मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाएं। ऊपर से इस काम को कराने का आदेश आये और वे एक बड़ी धनराशि का काम कराकर इस पुल को चालू करा दें। एमसीएफ के आला अफसर चाहते हैं कि इस पर राजनीतिक निर्णय हो। उन्हें जनता की तकलीफ से मतलब नहीं है। फरीदाबाद के कम से कम तीन विधायकों और एक अदद केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूर्जर और उनके बेटे सीनियर डिप्टी मेयर देवेन्द्र चौधरी का इस पुल से सीधा सरोकार है लेकिन इनमें से किसी नेता ने भी इस पुल की मरम्मत यथाशीघ्र कराने के बारे में मेयर और कमिश्नर से बात नहीं की। बडखल की विधायक सीमा त्रिखा को एनआईटी इलाके के अवैध निर्माणों की चिन्ता है तो ओल्ड फरीदाबाद के विधायक नरेन्द्र गुप्ता को सेक्टरों के पार्कों की और एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा को फैक्ट्री गेट पर मीटिंग करने और सोहना रोड की राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। इन्होंने भी नीलम पुल के लिए आवाज बुलंद नहीं की।

आपका-हमारा सरोकार

आंगनवाड़ी के बुरे हालात

हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्करों के हालात बहुत बुरे हैं। उन्हें केन्द्र से मिलने वाला मानदेय अप्रैल 2020 से और राज्य से मिलने वाला मानदेय भत्ता भी पिछले दो महीने से नहीं मिला है। आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया पिछले दो साल से नहीं मिला है। तमाम ड्यूटी जबरन लगाई जा रही है। कोरोना, बीएलओ व अन्य कोई भी काम जो छह सेवाओं व पांच उद्देश्य से अलग है वो भी डयूटी बिना विभाग के पत्र के जबरदस्ती लगाई जाती है, जिसका कोई मेहनताना नही दिया जाता है। आगनवाडी केन्द्रों में आने वाला राशन एक ही जगह पर डाल दिया जाता है। वर्करो से राशन की रिसीविगं नहीं ली जाती ओर राशन तौल मे भी कम आता है।

विकलांग आरक्षण में नाइंसाफी

हरियाणा सरकार ने विकलांगों के साथ मनमानी करते हुए हरियाणा ग्रुप डी 2018 में विकलांगों को सिर्फ तीन फीसदी आरक्षण दिया जबकि विकलांगों का रिजर्वेशन 4 फीसदी का है। इसकी जानकारी अब निकल कर आ रही है। हालांकि मोदी और भाजपा दिव्यांगों का हितैषी होने का दम भरते हैं लेकिन जब विकलांगों को ग्रुप डी परीक्षा में मौका देने की बारी आई तो उनका हक ही मार लिया गया।

गतांक की चीर-फ़ाड़

किसान आंदोलन के विभीषण : पंजाब का अकाली दल और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 6-12 दिसम्बर के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक व सामाजिक समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार द्वारा कृषि ढांचा बदलने और किसानों की स्थिति में सुधार लाने के नाम पर बनाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों तथा कॉरपोरेट घरानों के विरुद्ध पंजाब के किसानों के नेतृत्व में देश भर के किसान महीनों से आंदोलित हैं। उनको आशंका है कि ये तीनों कानून उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। देश में पहली बार किसानों का मुद्दा राजनीति के केन्द्र में आया है। इस समय किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर मोर्चा लगा कर बैठे हैं। 'कारपोरेट दलाल मोदी सरकार से किसान न उगलते बन रहे न निगलते बन रहे दो दौर की बात-चीत नाकाम, कितने दौर और होंगे।' में किसान आंदोलन के विभिन्न पक्षों का तार्किक विश्लेषण किया गया है।

किसान आंदोलन में पंजाब के अकाली दल और हरियाणा की जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) की अवसरवादिता को 'किसान राजनीति के दो बदनाम दाग-अकाली दल और जेजेपी' में बेनकाब किया गया है। जब तीनों किसान विरोधी कानूनों के बिल लोकसभा में लाए गए तब अकाली दल सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल के बेटे की पत्नी केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर एक बार भी इस बिल के खिलाफ़ नहीं बोली तथा उनके पति सुखबीर सिंह बादल और ससुर प्रकाश सिंह बादल चुप रहे। अब प्रकाश सिंह बादल अपना पद्मभूषण सम्मान लौटा कर किसानों के मुद्दे पर मसीहा बनना चाहते हैं। आश्चर्य है कि स्वदेशी और राष्ट्रवाद के पैरोकार व्यवसायी योग गुरू रामदेव की पतंजलि कंपनी के उत्पाद में मिलावट पाई गई है। पतंजलि के उत्पाद पहले भी लैब जांच में फेल हो चुके हैं और पतंजलि कंपनी पर अनेक अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं, जिनका 'लाला रामदेव साबित हुए मिलावटी बाबा-पतंजलि के नाम पर बेचती है शक्कर' तथा मोदी ने तो लाला को बहुत पहले ही पहचान लिया था' में पर्दाफ़ाश किया गया है।

दरअसल रामदेव की पतंजलि कंपनी का व्यवसाय घोर अनियमितताओं और उत्पादों में मिलावट तथा टैक्स चोरी के आरोपों के बावजूद संघ परिवार व मोदी सरकार के संरक्षण में फ़लता-फुलता जा रहा है। कुछ भी हो, मिलावट खोरी पर शिकंजा कसा जाना जरूरी है। ज्यादा पैसा कमाने के लालच लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मुनाफ़ाखोरो को बख्शा नहीं जाना चाहिये।

मज़दूर मोर्चा के संपादक सतीश कुमार ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर फ़रीदाबाद के ट्रेड यूनियन आन्दोलन के इतिहास की श्रंखला प्रकाशित करके मज़दूरों की वास्तविक दशा ओर विभिन्न ट्रेड यूनियनों की गतिविधियों से पाठकों को परिचित कराने के सराहनीय कार्य करने के साथ-साथ 'मज़दूर मोर्चा' के नाम को सार्थक किया है।

पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने भाजपा और संघ के विरोध के नाम पर जनता से वोट लेकर भी भाजपा से गठबंधन कर लिया था। किसान आन्दोलन के प्रति स्पष्ट रूख न अपनाने के कारण जेजेपी के पांच विधायकों तथा जेजेपी के कई पदाधिकारियों द्वारा किसान आन्दोलन का समर्थन करने के फलस्वरूप उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का अपना आधार खिसकता नज़र आया। इसलिये जेजेपी अध्यक्ष निशान सिंह और जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने गृहमंत्री अनिल विज से मुलाकात कर किसानों पर दर्ज मुकदमें वापिस लेने की मांग की तथा कहा कि सरकार को किसानों की मांगों की ओर ध्यान देना चाहिये।

कोरोना आपदा के दौर में इम्यूनीटी बढ़ाने के लिये शहद का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है। लेकिन सेंटर फ़ॉर साईंस ऐंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की रिपोर्ट के मुताबिक, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की एनएमआर जांच में शहद के 13 ब्रैंड में 10 नामी ब्रैंड-पतंजलि, डाबर, बैद्यनाथ, हितकारी, झन्डू, हिमालय आदि-फेल हो गए। जांच से पता चला कि शहद में चावल और गन्ने से बना चीन की कम्पनियों का शूगर सिरप मिलाया गया हे।

अभी तक मोदी सरकार ओर किसानों के प्रतिनिधियों के बीच पांच दौर की बेनतीजा बात-चीत हो चुकी है। छठे दौर की बात-चीत 9 दिसम्बर को हुई। दरअसल सरकार मन बनाकर बैठी है कि वह किसानों की जरूरत के अलावा सब बातें मान लेगी, लेकिन किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने से कम पर तैयार नहीं। सरकार अभी भी पुराने खेल में व्यस्त है कि आंदोलन को व्यस्त किया जाए तथा आंदोलनकारियों को आपस में लड़ाया जाए या बहकाया जाए या फ़िर थका दिया जाए। लेकिन किसान सरकार की चालों के प्रति सजग हैं।